very complex process. We are attending to the issue and the RBI and NABARD are engaged in it. so, I can't give an off-hand answer unless we draw some conclusions. Sir, we have given debt relief. There is no proposal at the moment to do a debt write-off. My earnest request, Sir, is let us give this package a fair trial. Let us review the matter after about three-four months.

SHRI LALITBHAI MEHTA: The Minister has already replied that nearly 140 banks are in red. I would like to know from the hon. Minister whether the previous Government had made any special package or provision in the last Budget to the tune of Rs. 8000 crores for the revival of these district cooperative banks, including the urban cooperative banks. If so, whether any progress has been made in this matter and which are the proposals that the Ministry has received. How many banks have been helped?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, there was a proposal to restructure the finances of cooperative banks. I have, in my Budget speech, said that we will appoint a task force which should be asked to give its report by 31st of october. I am in the process of appointing that task force. Further action on the previous Government's proposal as well as what we have in mind can only be taken after the task force report is received by 31st of October. ...(*Interruptions*)...

SHRI LALITBHAI MEHTA: whether those proposals have been processed and examined. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Next question. Question No. 209; Shrimati Sarla Maheshwari.

Increase in area under Irrigation

*209. SHRIMATI SARLA MAHESHWARI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) what is the increase in the land area under irrigation during the last three years;

(b) whether Government are having any short-term plan for the extension of irrigation facilities; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

As per provisional assessment made by the Ministry of Agriculture, the increase in area under irrigation during the last three years, *i.e.* during 2001-02 to 2003-04 is of the order of 3.69 million hectare.

Irrigation being a State subject, the responsibility of planning, execution and funding of all types of irrigation projects including drawing up of any short term plan for extension of irrigation facilities primarily rests with the State Governments. However, for early completion of ongoing major and medium irrigation projects, Government of India provides Central Loan Assistance (CLA) to the State Governments under the Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) since 1996-97. CLA under AIBP is also provided for the minor Irrigation schemes of the special category States comprising the North Eastern States and Sikkim, the hilly States of J&K, Himachal Pradesh and Uttaranchal as well as the drought prone Kalahandi, Bolangir and Koraput districts of Orissa with effect from 1999-2000.

The Finance Minister in his budget speech for 2004-05 has given due thrust to AIBP. Further, he has also announced launching of schemes for repair, renovation and restoration of all water bodies that are directly linked to agriculture and water harvesting schemes.

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, माननीय मंत्री जी के इस उत्तर के मद्देनजर कि तमाम निर्माणाधीन वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करेंगे। महोदयए, मैं इस 'शीघ्र पूरा करेंगे' को रेखांकित करना चाहती हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि हमारे देश में कोई भी सिंचाई परियोजना अपने नियत समय पर पूरी नहीं होती? अगर हां, तो क्या माननीय मंत्री इस पर रोशनी डालेंगे कि हमारे यहां मध्यम और वृहत सिंचाई परियोजनाएं कितनी हैं, जो लम्बित पड़ी हैं और इनके लम्बित पड़े रहने का क्या कारण है?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: सभापति महोदय, पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि सिंचाई का पूरा मसला राज्यों के दायरे में है। जब कोई सिंचाई की योजना, चाहे मध्यम हो या बड़ी हो, राज्य सरकार की तरफ से प्लानिंग कमीशन द्वारा आती है, तो हम उसमें अपना योगदान करते हैं और राज्य भी अपना योगदान करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रान्तीय सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण अपनी योजना के लिए वे हम से जो राशि लेते हैं, जो राशि हम देते हैं उसमें भी वे पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें उनकी राशि का योगदान नहीं हुआ होता है। इसको तुरंत ठीक करने के लिए 1996-97 में एक नई योजना लागू की गई थी। Accelerated Irrigation Benefit Programme इस योजना के द्वारा हमने इस काम को दोबारा तीन हिस्सों में बांटा। एक में हम उनके मेजर एंड माइनर प्रपोजल्स के द्वारा आइडेंटिफाई करेंगे। 8th प्लान में

मेजर 369, मीडियम 110 और 9th प्लान में 171 और 259 प्रोजेक्ट्स पूरे देश के लिए किए हैं। लेकिन इसमें जो दूसरा भाग है उनकी वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण हम लोग लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। हम लोग इस ओर लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने एक नया प्रोग्राम अपनाया जिसको Fast Track Programme कहते हैं। अगर स्टेट्स तुरन्त किसी प्रोग्राम को पूरा करना चाहती हैं तो वे खुद उनके बारे में पेशकश करें, जबकि ऐसी पेशकश ज्यादा स्टेटों ने नहीं की है। हम उसमें लोन के हिसाब से उनकी पूरे पैसों से सहायता करते हैं। प्लानिंग कमीशन ने स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल एरिया के लिए आइडेंटिफाई किया है, जिसमें नार्थ ईस्टर्न स्टेट, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। उड़ीसा में के.बी.के. के साथ। इनके तहत् हम काम करते हैं। योजना को पूरा करने के लिए नवीं योजना के अंतर्गत हमारा लक्ष्य निश्चित रेखा पार नहीं कर पाया, इसलिए इसकी मोनिटरिंग करने के लिए मैंने खुद दो आधार बनाए हैं। एक आधार के बारे में तो वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस साल लास्ट फाइव प्रोजेक्ट्स को पहले प्रायेरिटी के आधार पर पूरा करेंगे और लास्ट फाइव के बाद जो एक और प्रोजेक्ट है, उसे 2006 से पहले पूरा करेंगे। इनके बाद ही हम अगले प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेंगे।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, मैंने मंत्री जी से यह जानना चाहा था, सूची मांगी थी कि कितनी योजनाएं लंबित हैं और उनके लंबित होने के क्या-क्या कारण हैं? माननीय मंत्री जी ने एक उत्तर में तो यह कहा कि राज्यों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। राज्यों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आप इस बात पर विचार कर रहे हैं कि सिंचाई परियोजनाओं और राज्यों की वित्तीय स्थिति के संबंध में आप एक अध्ययन तैयार करें ताकि जो अटकी हुई योजनाएं हैं, इन अटकी हुई योजनाओं को तुरंत पूरा किया जा सके। इसके साथ ही मंत्री जी, मेरा एक दूसरा सवाल यह है कि विश्व स्तर पर बहुत से अध्ययन हुए हैं और उन अध्ययनों से यह पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय डैम माफिया काम कर रहे हैं, जो कि इन सिंचाई परियोजनाओं पर अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए तरह-तरह के खेल खेलते हैं, जान-बूझकर इन परियोजाओं में ढील देते हैं। क्या इस विषय में आपने अभी तक कोई अध्ययन किया है? क्या हमारे देश में भी इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय माफिया काम कर रहे हैं? क्या आपके पास इस तरह का कोई अध्ययन है, अगर है तो आप मुझे इसकी जानकारी दें?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: सभापति जी, जो योजनाएं पूरी नहीं हुई हैं, मैं उनके आंकड़े दे रहा हूं। आठवीं योजना में पूरे न हुए मेजर प्रोजेक्ट्स 171 हैं, मीडियम 259 हैं। कुल मिलाकर इन दोनों प्रोजेक्ट को कम्पलीट करके, जब नाइन्थ प्लान खत्म हुआ तो हमने देखा कि इसमें अभी मे 25 मेजर प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए और 45 मिडियम प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए। इन पर तुरंत काम करने के लिए, वित्त मंत्री जी की बजट स्पीच के अनुसार, जो

लास्ट के फाइव प्रोजेक्ट्स हैं, वे हम 2005 से पहले पूरा करना चाहते हैं और जो उसके बाद के प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें हम 2006 से पहले पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए सभी स्टेट्स के साथ बातचीत जारी है। अगस्त की दो तारीख को हम इस पर पूरा निर्णय लेंगे और देश की सिंचाई परियोजनाओं के साथ जुड़े पदाधिकारियों को हम दिल्ली में बुलाएंगे। जहां तक डैम माफिया की बात है, इसके लिए हमारी यू॰पी॰ए॰ सरकार कटिबद्ध है कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय माफिया हो या अंदर का माफिया हो, चाहे कोई भी हो; हम माफिया के सामने सिर नहीं झुकाएंगे।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: सभापति जी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बात कही है कि तुरंत सिंचाई लाभ कार्यक्रम ए॰आई॰बी॰पी॰ के तहत केंद्रीय ऋण मुहैया कराया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर पूर्व के राज्यों को कितनी राशि केंद्रीय ऋण वित्तीय सहायता के अंतर्गत दी गई है?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: सभापति महोदय, फिलहाल पूरे देश में इस स्कीम के आधार पर 14670.233 करोड़ रुपए की राशि हम बांट चुके हैं। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में अभी तक 1505.003 करोड़ राशि दे चुके हैं, जहां तक उड़ीसा का सवाल है तो उड़ीसा को हम 898.250 करोड़ राशि दे चुके हैं...(व्यवधान)...

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: मैंने उत्तर-पूर्व के राज्यों के बारे में भी पूछा है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: उत्तर-पूर्व के राज्यों पर भी आऊंगा, अभी मैं एक-एक करके बता रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश को 51.500 करोड़ रुपए, असम को 120.1933 करोड़ रुपए, नागालैण्ड को 23 करोड़, मेघालय को 14 करोड़, मणिपुर को 15 करोड़ से ज्यादा राशि दी है, त्रिपुरा को 20 करोड़ की राशि हमने उपलब्ध कराई है। फिलहाल जो आंकड़े हैं उसमें सिक्किम को भी हमने 5.260 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं।

डा॰ प्रभा ठाकुर: सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि राजस्थान जैसा प्रदेश, जहां पिछले चार वर्षों से निरंतर अकाल पड़ने के कारण ...। वहां सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि के स्थान पर कमी आ गयी है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जल-संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान जैसे आपदाग्रस्त राज्यों को क्या माननीय मंत्री जी किसी विशेष श्रेणी का दर्जा देकर जल-संसाधनों के लिए विशेष सुविधा और सहायता देने का विचार रखते हैं?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: सभापति महोदय, इस मसले पर फैसला प्लानिंग कमीशन करता है और प्लानिंग कमीशन के वर्तमान फैसले के अनुसार सिर्फ नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स

श्री सभापति: आप देना चाहते हैं या नहीं, यह बता दीजिए क्योंकि Question Hour खत्म हो रहा है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: सभापति महोदय, सूखाग्रस्त इलाके के बारे में हम नया चिंतन शुरू कर रहे हैं और इस बारे में अगले महीने निर्णय लेने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा।

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over. Papers to be laid on the Table.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

ONGC'S Joint venture in Sudan

*201. SHRI RAJKUMAR DHOOT: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that commercial poduction of crude oil in Sudan through joint ventures of ONGC Videsh and Sudanese Government has started;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the quantity and the rate at which crude oil from Sudan will be available to India?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI MANI SHANKAR AIYAR): (a) and (b) Of the three Joint Ventures (JVs) formed by ONGC-Videsh Limited (OVL) in E&P projects in Sudan, only the Greater Nile Oil Project (GNOP) is in commercial production. When OVL acquired 25% stake in the GNOP, Sudan on 12.3.2003, the project was already in commercial production.

(c) The total annual crude oil production from GNOP, Sudan during 2003-04 was 13.291 million metric tons (MMT), out of which OVL's equity share was 3.323 MMT. Out of the projected annual production of 14.50 MMT of crude oil from the project for the year 2004-05, OVL's equity share would be 3.625 MMT.

After making provisions for statutory levies like royalty, taxes, etc., to the Government of Sudan, the balance crude oil is available to OVL for sale at prevailing market price.